भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1110

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल्स ऑन व्हील्स

1110. डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास झारखंड में ग्रामीण युवाओं की विशिष्ट आकांक्षाओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए कोई पहल मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उन ग्रामीण युवाओं को कौशल बढ़ाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोई योजना है जो अपने गांवों में रहना पसंद करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में "स्किल्स ऑन व्हील्स" जैसी मौजूदा पहलों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि उनके घरों के करीब कौशल उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण युवाओं के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन दर कितनी है; और

(च) झारखंड में इन कार्यक्रमों की जागरूकता और पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत कुशल भारत मिशन (सिम), विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और अप-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से, झारखंड के ग्रामीण युवाओं सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य गैर-साक्षरों, नव-साक्षरों और 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के 12वीं कक्षा तक शिक्षा के अल्पविकसित स्तर और स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें "दिव्यांगजनों" और अन्य योग्य मामलों के मामले में उचित आयु में छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और नौकरी पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ): युवा आबादी को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से, एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) झारखंड के रांची में 'स्किल ऑन व्हील्स' कार्यक्रम चला रहा है। इस पहल

का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के क्षेत्रों में व्यक्तियों को उनकी नियोजनीयता में सुधार के लिए कौशल तक पहुँच प्राप्त हो।

(ड.) और (च): एमएसडीई ने जागरूकता अभियान, कार्यशालाओं और सामुदायिक सहभागिता पहल के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में कौशल विकास के लिए कार्यक्रमों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई हैं। कौशल पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), माईगॉव और दूरदर्शन (डीडी) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से भी किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, मंत्रालय ने कौशल से संबंधित जानकारी और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में व्यक्तियों को लाभ हुआ है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जानकारी और नामांकन चाहने वाले युवाओं के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन संसाधन के रूप में कार्य करता है। इस मंच के माध्यम से पहुंच में आसानी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

2023-24 के दौरान एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है:

	पीएमकेवीवाई	**जेएसएस**	**एनएपीस***	**सीटीएस (आईआईटी)**
अखिल भारतीय	5,39,325	5,07337	9,32,298	14,46,247
झारखंड	8,796	22,439	11,882	40,103

*प्रशिक्षु नियोजित

****